need for a long-term planning in the transportation sector has initiated a process for the preparation of a perspective transportation plan duly integrated with the various sectors of the economy. In planning for the future, special emphasis is being placed on technological upgradation with a view to absorb emerging technologies and improve productivity and efficiency of the services. As part of this process, the Commission had set up a Committee of experts to organise specific studies for evolving a broad policy framework and institutional measures to systematise work on long-term plans on a continuing basis. The Committee has since submitted its report which should hopefully provide requisite input into the work of the concerned Ministries to develop their corporate plans.

Legislative measures for implementation of reservation policy

1516. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact a new legislation so that those officers who are found guilty of not fulfilling the constiutional guarantee and governmental directives regarding reservation of posts for Scheduled Caste/Scheduled Tribe, are made punishable;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir.

(c) The existing executive instructions are considered sufficient to implement the Government policy on reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and also to take care of violation of Constitutional safegurards

ग्राम न्यायालयों की स्थापना

1517. **श्री अजीत जोगी :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री 5 मई, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1052 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध मे क्या प्रगति हुई है और ऐसे न्यायालयों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ख) ग्राम न्यायालयो के माध्यम से लगभग कितने प्रतिशत मामलों का निपटान किया जाएगा और इससे अन्य न्यायालयों का भार कितना कम हो जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर अभी विचार कर रही है । तथापि, इस समय सरकार के लिए यह बताना संभव नहीं है कि ऐसे न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे और उनसे अन्य न्यायालयों का भार कितना कम होगा ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1518. **श्री अजीत जोगी :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री 24 मार्च, 1988 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 428 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों तथा अपर न्यायाधीशों के रिक्त पडे चार पदों को भरे जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इन रिक्त पदों मे से कोई पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को दिए जाएंगे ?